भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1564

दिनांक 28.07.2026 को उत्तरार्थ

पंचायतों में डिजिटल अवसरंचना का विकास

†1564. श्री विजय कुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पंचायतों और शहरों के बीच संपर्क में सुधार के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो विकसित की गई सड़कों, परिवहन और डिजिटल अवसंरचना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या ग्रामीण-शहरी संपर्क को बढ़ाने के लिए कोई जिला-वार योजना मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो पंचायतों को समीपस्थ शहरी केंद्रों से जोड़ने वाले एकीकृत नियोजन की कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्रामीण सड़कों और परिवहन सेवाओं जैसी योजनाओं ने वांछित संपर्क परिणाम हासिल किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ग्रामीण आवागमन और पहुंच को प्रभावित करने वाली इनकी कमियों के क्या कारण हैं;

(घ) क्या पंचायत से शहर से संपर्क में सुधार के लिए पर्याप्त निधि आवंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस हेतु अपर्याप्त निधि के क्या कारण हैं जो अवसंरचना विकास को प्रभावित कर रही है; और

(ङ) क्या सरकार ने पंचायतों से प्रमुख शहरों तक अंतिम छोर तक संपर्क सुनिश्चित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो परिवहन नेटवर्क में लगातार बनी हुई कमियों के क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ङ) यह विषय पंचायती राज मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।

यद्यपि, मंत्रालय संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु कंप्यूटर सुविधाएँ उपलब्ध कराकर तथा सीमित स्तर पर पंचायत कार्यालय परिसर में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के सह- स्थापन द्वारा सेवा प्रदाय को सुगम बनाता है। वर्ष 2022–26 की अवधि के लिए, योजना के अंतर्गत 29 राज्यों एवं 5 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 65,345 कंप्यूटरों की स्वीकृति प्रदान की गई तथा पंचायत कार्यालय परिसरों में 17,547 कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के सह-स्थापन की स्वीकृति दी गई।

इसके अतिरिक्त, पंचायतों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल इंडिया पहल के तहत, पंचायती राज मंत्रालय ने देश के स्थानीय ग्रामीण शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यदक्षता लाने के लिए विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप विकसित किए हैं। इस मंत्रालय ने ईग्रामस्वराज पोर्टल (https://egramswaraj.gov.in) शुरू किया है, जो एक उपयोगकर्ता के अनुकूल वेब-आधारित पोर्टल है। इसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन, कार्य-आधारित लेखांकन और सृजित परिसंपत्तियों के विवरण में बेहतर पारदर्शिता लाना है। इस ऐप को सार्वजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली, सरकारी ई-मार्केटप्लेस और ऑडिटऑनलाइन ऐप के साथ एकीकृत किया गया है ताकि भुगतान सुगम हो, खरीद में पारदर्शिता हो और पंचायतों के खातों की लेखापरीक्षा की जा सके।

पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत के स्वयं के राजस्व स्रोत संग्रह को डिजिटल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म "समर्थ पंचायत पोर्टल" विकसित किया है जो कर और गैर-कर मांगों के सृजन और संग्रह, कर रजिस्टरों के रखरखाव और राजस्व की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह डिजिटल सशक्तिकरण स्थानीय वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और मापनीयता लाने के लिए बनाया गया है।

****